माँ

BINDU RAJAGOPAL

S.

प्यारी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ
तू ही है, बस तू ही
मुझे ममता देने वाली
ओ मेरी प्यारी माँ ।

दुख सुख और पढाई में
हर वक्त साथ रहने वाली
तू ने संसार दिखाया,
सीधे रास्ते पर लायी ।

तेरे प्यार से मैं दब गयी
इसके बिना मैं क्या होती,
यह मैं सोच भी नहीं सकती
ओ मेरी प्यारी माँ ।

इसके बदले मैं तुझे
मैं क्या दे सकती बोल ?
तू ही मेरी देवी है
तू ही मेरी सब कुछ है ।

राष्ट्रीय एकीकरण

NAVEEN MADHU

III B. Com.

"एकता में बल है"—यह वाक्य कितना सार्थक है। आज का हर भारतीय इस वाक्य को जैसे भूल ही गया है। श्रीमती इन्दिरागाँधी की निर्दय हत्या और उसके बाद दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्रों में हुए साम्प्रदायिक दंगे यह साफ जाहिर करते हैं कि भारतीयों के बीच एकता कितनी कमजोर हो गई है तथा साम्प्रदायिक बरबादियों से आम जनता का जीना कितना मुशकिल हो गया है। एक प्रजातंत्र राष्ट्र में इससे बडी दुखपूर्ण घटना और क्या हो सकती है जब उसके अपने चुने हुए नेता की बदली मतदान के बदले गोलियों की बौछार से की गयी हो। यह घटना हर नागरिक के लिए पाठ है कि जिस प्रजातंत्र देश के प्रधान मंत्री को बन्दूक से हटाया जा सकता है उस देश में प्रजातंत्र का अर्थ ही व्यर्थ हो जाता है। राष्ट्रीय एकता पर अटूट विश्वास रखनेवाली श्रीमती गाँधी भी इस एकता को सबल बनाते बनाते शहीद हो गयीं। इसीलिए शहीद हुई कि उन्हों ने पंजाब के आतंकवादियों के साथ ईटं से ईटं बजा दिया था।

आजकल साम्प्रदायक दंगो प्रत्येक नागरिक के ऊपर फाँसी के फँदे की तरह छाये हुए हैं। हमें इन दंगों की बू आएगी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की एकता गहरे संकट में है। इसके उत्तरदायी क्या केवल पंजाब के आतंकवादी, महाराष्ट्र की शिव सेना आदि ही है? या आप जैसे, मुझ जैसे प्रत्येक नागरिक उत्तरदायी है? क्या दक्षिण का मद्रासी उत्तर के पंजाबी को अपना भाई मानेगा? क्या उच्चवर्ग का एक व्यक्ति एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करेगा? इन प्रश्नों का उत्तर सन्तोषजनक नहीं होगा।

भारतवर्ष का प्रात्येक मनुष्य अगर एक दूसरे का उपकार करे तो उस से ही परस्पर एकता बढेगी। इसलिए उसकी महिमा इसी में है कि वह दूसरों के लिए जीना तथा मरना सीखे।

"परोपकरार्थं फलन्ति वृक्ष : परोपकारार्थं बहन्ति नद्या:।

परोपकारार्थं दुहन्ति गोव :परोपकारार्थं मिदं शरीर:।।

वास्तव में परोपकार की प्रवृत्ति में एकता की भावना रहती है। अत : जहाँ परोपकार नही, वहाँ एकता कहाँ हो सकती है?

भारत एक जटिल समाज है जिसमें असंख्य भाषाएँ धर्म एवं संस्कृतियाँ वर्षों से चली आ रही हैं। तब यहाँ छोटे-बडे झगडे तो स्वाभाविक हा हैं। धार्मिक एवं वर्गीय दंगे भी हो सकते हैं। हर दंगे के बाद नेता बडी चाव से राष्ट्रीय एकता पर भाषण देते हैं। इसके अतिरिक्त सभाओं का आयोजन होता है।... बस। कुछ समय बाद दंगे फिर से दुहुराये जाते हैं। केवल शपथ लेने तथाविचार विमर्श से एकीकरण कहाँ से आएगा।

हमारे देश की खूबा यह है कि यहाँ पर पंजाबी हैं मराठो हैं, मलयाली हैं, सब हैं। लेकिन एक भारतीय का यहाँ मिलना कठिन है। इसलिए पहले हम सब को भारतीय बनना पडेगा। लेकिन जब तक यहाँ नेता भेडे को खाल में छुपे भोडिये बन विचरते हैं, तब तक ऐसा होना कठिन है। एक ओर से ये राष्ट्रीय एकीकरण की बातें करते हैं तो दूसरी ओर अपने स्वार्थलाभ के लिए साम्प्रदायिक दंगों को उभाडते हैं। जिसप्रकार ज्वालामुखी धरती की मुलायम जगह को तोडकर नाश करती है, उसीप्रकार अधिकार लोलुप नेता लोग धर्म, जाति आदि पर चोटकर हर जगह आशांति फैलाते हैं।

इस साम्प्रदायिकता को हटा कर राष्ट्रीय एकीकरण करना नाकों चने चबाने के बराबर है। केवल एक भाषा का प्रयोग न करना इस समस्या की और भी जटिल बना रहा है। शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में एक हो भाषा का प्रयेगो होना चाहिए। हर क्षेत्र में चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए न कि जाति एवं पैसे के बल पर।

लेकिन इनके पहले कुछ अन्य समस्याओं को भी सुलझाना है — गरीबी और अज्ञान। इन दोनों का आगर समाधान न हुआतब शेष के संबन्ध में सोचना ही कठिन है।

कुछ बाहरी ताकतें भी भारन की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को गहरी चोट पहुँचा रही हैं। धर्म को लेकर यहाँ कुछ लोग बिगडी हुई स्थिति को और भी बिगाड रहे हैं। अत : इन समस्याओं को सुलझाने में और भी समझदारी चाहिए। केवल सर्कार इन समस्याओं का हल कभी नहीं कर सकती।

भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपनी मातृभूमि को सुदृढ बनाये। अगर एक पागल सिख ने हमारी प्रिय नेता का वध किया तो इसमें अन्य सिखों का क्या दोष हैं? क्या बापू और चाचा नेहरू ने हमें यही संदेश दिया था? हमें अपने प्रिय नेताओं के आदेशों पर चलना चाहिए और अपने खून को एक एक बूँद को राष्ट्र के एकीकरण के लिए भेंट कर देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य रहेगा और यही हमारा दृढ निश्चय रहेगा।

उच्च शिक्षा और भारत

— ATHIK AHAMED FAROOQUI
II BSc (Chem)

उच्च शिक्षा की प्रगति हर देश के भविष्य और उन्नति का मापदण्ड है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ''अगर बिश्वविद्यालयों मे सब ठीक है, तो अवश्य देश में भी सब ठीक होगा।

जहाँ तक संख्या में बढौती का मसाल है, भरतीय 'रेकार्ड' काफो प्रशंसनीय है। उच्च शिक्षा मे छात्रों की संख्या हर साल 9·2 प्रतिशत से बढ रही है। उच्च शिक्षा के हर विभाग मे छात्रों की संख्या मे बढत हुई है। लडकियों की संख्या इस क्षेत्र में कराब 17 गुना बढ गई है। भारत मे कई राज्यों मे उद्योगों की काफी उन्नति हुई है। इन राज्यों में पोलीटेकनिक और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रों कीसंख्या बहुत बढ गई है।

छात्रों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की इस बढौती के कारण सरकार को बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड रहा है। इसमें से आधे से भी ज्यादा भाग कर्मचारीयों की वेतन देने के लिए खर्च किया जाता है।

छात्रा ओर कालेजों का संख्यावृद्धि कई कठिनाईयाँ भी लायी हैं।

आजकल छात्रों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ रही है। कालेजो की संख्या भी इस कारण बढती रहती है। नए नए कालेज शुरू किए जा रहे है। पुराने कालेजो में हर साल छात्रों की संख्या बढाई जाती है। भारत में जो नियमित व्यवस्था है उसके अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा चलाते हैं। इस बढती हुई संख्या के कारण आज हम ऐसी स्थिति देख रहें हैं कि विश्वविद्यालय सिर्फ एक परीक्षा केन्द्र बन गया है। विश्वविद्यालयो का लक्ष्य है – ''उच्च शिक्षा की उन्नति करना''। लेकिन इस लक्ष्य को आज कोई महत्व नही दिया जाता है। इस स्थिति को मिटाने के लिए यह जरूरी है कि एक अलग संस्था की स्थापना की जाए। इस संस्था का काम परीक्षा। सम्बन्धित कार्य की देख रेख करना होगा। इस तरह की संस्था की स्थापना के बाद ही विश्वविद्यालय अपने बुनियादी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

आर्थिक दृष्टि से खेती-बाडी भारत की रीढ है। आधे से भी ज्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा की संस्थाएँ आम तौर पर शहरों मे ही होती हैं। जो संस्थाएँ पिछडे इलाकों मे हैं उनमें ऐसे विषय पढाये जाते हैं जिससे गाँव वालों को अधिक फायदा नहीं होता। जब उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या हर साल करीब 9.2 प्रतिशत से बढी है तब कृषि विद्यालयो में सिर्फ 2.6 प्रतिशत से वृद्धि हुई है। इसका यह कारण है कि कृषि पढानेवाली संस्थाओं की कमी है। गाँवों में स्थित संस्थाओं में परमाणु—शक्ति जैसे विषय पढाए जाते हैं। यह ठीक नहीं है गाँवों मे बयो गैस और कम धुआँ-वाले चूल्हो की जरूरत है। यह सब दृष्टि में रखकर पिछडे इलाकों में एसी उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जो उन इलाकों की प्रगति करें।

जो धन राशि विश्वविद्यालयों के लिए दी जाती है, उसमे से बडा हिस्सा कर्मचारोयों के वेतन पर खर्च किया जाता है। शोधकार्य और नए उपकरण खरीदने के लिए बहुत कम पैसा बच जाता है। इस कारण विश्वविद्यालयों में बहुत से अच्छे अध्यापक जिन्हे शोध करने का उत्साह होता है निराश होते हैं। कई विदेश मे चले जाते हैं जहाँ उच्च स्तर का शोध कार्य करने की सुविधाएँ रहती हैं। इसमे हमारे विश्वविद्यालय और देश का ही नुकसान है। कई केन्द्र ओर राज्य सरकार द्वारा चलाई जानेवाली शोध

संस्थाओं मे शामिल हो जाते हैं। इससे विश्वविद्यालयो का बहुत नुकसान है। यह हालत बदलनी चाहिए। इस देश की प्रतिभा यहीं रहे, यहीं रहकर देश की प्रगति के लिए प्रयत्न करे, ऐसी अवस्था होनी चाहिए।

कालेज और विश्वविद्यालयो मे राजनैतिक दल घुस आए है और कालेज 'यूनियन' आदि पर काबू कर चुके हैं। यह उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए बाधा है। विद्यार्थीयो का अपना संगठन होना चाहिए। मगर यह ज़रूरी नहीं कि यह संगठन राजनैतिक दलों के विद्यार्थी संघ की तरह पेश आएँ। जो व्यक्ति कालेज--यूनियन चुनाव मे बिजय पाता है, वह अपने बल पर नहीं, बल्कि जिस पार्टी का उम्मीदवरा बनके वह खडा होता है उसके बल पर विजयी होता है। ऐसा व्यक्ति विधार्थी की भलाई के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं कर सकता। बहुत लोग कहते है कि कालेज और विश्वविद्यालयो से राजनैतिक दलों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नही सुझाया जा रहा है जिसे आसानी से लागू किया जा सके। राजनैतिक दलों को विश्वविद्यालयों से दूर रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नीति बनाई हैं कि 'सेनेट' मे सिर्फ सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे जो उच्च शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण योग दे सकेंगे। कई सरकारों ने इस नीति को अपनाया भोहै। लेकिन जो सदस्य नियुक्त किये गये हैं वे भी राज़नैतिक दलों के सदस्य हैं। इनमे से बहुतोंने कालेज का मुँह तक नहीं देखा है। इस तरह के लोग उच्च शिक्षा। की प्रगति में क्या योग दे सकेंगे ?

जैसे पहले बताया गया अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जब विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षा संचालन केन्द्र बन गया है। विधार्थीयो में अनुशासन भी बद गया है। सरकार एसे उप कूलपतियो को नियुक्त कर रही है जो आई-ए-एस या आई पी एसहो। इस तरह के व्यक्ति अनुशासन और परीक्षा सम्बन्धित कार्य ठीक तरह से कर पाएँगे। मगर शोध कार्य में अध्यापकों और शोध छात्रा को नेतृत्व, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन नहीं दे पाएँगे।

इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत की उच्च-शिक्षा क्षेत्र एक दिशा-संधि पर है। एडी से चोटी तक अनेक दोष देख सकते हैं। इन सब का विशद विश्लेषण कर इनके निवारण के लिए प्रयत्न करने का समय आया है। क्यों कि इक्कीसवीं शताब्दी की ओर कदम बढाने वाली एक जनता के लिए बिल्कुल अनुरूप नहीं है हमारी उच्च शिक्षा पद्धति। यदि हम देश और काल के अनुरूप बदलने को तैयार नहीं हैं तो यह आनेवाली पीढी के प्रति किया जानेवाला अक्षम्य अपराध होगा।